पंजाब केसरी
TUE,24 MARCH 2026
EDITION: KANGRA KESARI, PAGE NO. 3

स्कूलों में पढ़ाया जाएगा हिमाचल का इतिहास और आधुनिक खेती

एन.सी.वी.टी. को भेजा गया प्रस्ताव, जल्द शुरू करने की तैयारी

धर्मशाला, 23 मार्च (समियाल): हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला राज्य के युवाओं को अपनी मिट्टी और स्थानीय संसाधनों से जोड़ने के लिए स्कूली शिक्षा में हिमाचल का इतिहास और बागवानी को व्यावसायिक विषय के रूप में शुरू करने की तैयारी कर रहा है।

इस नई योजना के तहत सबसे पहले प्रदेश के गौरवशाली इतिहास और समृद्ध संस्कृति को एक विशेष विषय के रूप में पाठ्यक्रम में शामिल करने का प्रस्ताव है, ताकि छात्र अपनी जड़ों, नदियों और परंपराओं की विस्तृत जानकारी हासिल कर सकें।

इसके साथ ही प्रदेश की आर्थिकी को मजबूती देने के लिए कक्षा 9वीं से 12वीं तक बागवानी को भी दूसरे व्यावसायिक विषय के रूप में शुरू करने की योजना बनाई गई है। प्रस्तावित पाठ्यक्रम को अंतिम मंजूरी के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद को भेजा गया है। इसे जल्द शुरू करने की तैयारी की जा रही है।

दरअसल बोर्ड को हाल ही में ड्यूल कैटेगरी का स्टेटस मिला है, जिससे उसे राज्य की भौगोलिक और आर्थिक जरूरतों के अनुरूप व्यावसायिक पाठ्यक्रम तैयार करने का अधिकार मिला है। इसी के तहत हिमाचल के गौरवशाली इतिहास और बागवानी को स्कूली स्तर पर शामिल करने का फैसला लिया गया है।

शिक्षा बोर्ड ने इस नए पाठ्यक्रम को छात्रों की आयु और समझने की क्षमता के आधार पर 2 विशेष चरणों में विभाजित किया है। योजना के अनुसार कक्षा 9वीं और 10वीं के विद्यार्थियों को बागवानी और प्रदेश की संस्कृति की बेसिक स्टडी (प्रारंभिक शिक्षा) करवाई जाएगी, ताकि वे कम उम्र में ही अपनी मिट्टी और गौरवशाली इतिहास की बुनियादी जानकारी हासिल कर सकें। वहीं, कक्षा 11वीं और 12वीं के छात्रों के लिए एडवांस स्टडी का प्रावधान रखा गया है।

उल्लेखनीय है कि वर्तमान में आंध्र प्रदेश देश का एकमात्र ऐसा राज्य है, जहां बच्चों को उनके अपने राज्य का विशेष इतिहास पढ़ाया जाता है। यदि एन.सी.वी.टी. से इस प्रस्ताव को अंतिम मंजूरी मिल जाती है तो हिमाचल प्रदेश अपनी विरासत से बच्चों को रू-ब-रू करवाने वाला देश का दूसरा राज्य बन जाएगा।

बोर्ड को मिला 'ड्यूल कैटेगरी' का विशेष अधिकार

यह बदलाव इसलिए संभव हो पाया है क्योंकि स्कूल शिक्षा बोर्ड को हाल ही में ड्यूल कैटेगरी का स्टेटस मिला है। इस अधिकार के मिलने से बोर्ड अब राज्य की भौगोलिक और आर्थिक जरूरतों के अनुरूप खुद के व्यावसायिक पाठ्यक्रम तैयार कर सकता है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य युवाओं को अपनी जड़ों से जोड़ना और उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है।

स्कूल शिक्षा बोर्ड ने हिमाचल के इतिहास, संस्कृति और बागवानी को नए विषय के रूप में शामिल करने का प्रस्ताव मंजूरी के लिए भेज दिया है। ड्यूल कैटेगरी स्टेटस मिलने के बाद बोर्ड अब राज्य विशेष कौशल विकास पर मुख्य रूप से फोकस कर रहा है। चूंकि हिमाचल प्रदेश में बागवानी एक मुख्य व्यवसाय है, इसलिए इसे 9वीं से 12वीं कक्षा तक शुरू करना विद्यार्थियों के भविष्य के लिए मील का पत्थर साबित होगा। हमारी योजना इसे आगामी सत्र से पूरी तरह लागू करने की है।

–डा. राजेश शर्मा, अध्यक्ष, स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला।

मूल्यांकन केंद्रों में ड्यूटी के लिए चयनित शिक्षकों का डाटा मांगा

दिव्य हिमाचल ब्यूरो-धर्मशाला

- दो दिन में रिपोर्ट भेजने के आदेश जारी
- बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम समय पर देने की तैयारी

राजेश शर्मा

हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने वार्षिक परीक्षाओं के परिणामों को समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से घोषित करने की दिशा में अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। बोर्ड अध्यक्ष डा. राजेश शर्मा ने सभी जिला उप-निदेशालयों को कड़े निर्देश दिए हैं कि वे स्पॉट मूल्यांकन केंद्रों में ड्यूटी के लिए चयनित शिक्षकों की सूची आगामी दो दिन के भीतर बोर्ड को भेजना सुनिश्चित करें।

चेतावनी **बोर्ड अध्यक्ष ने स्पष्ट** किया कि जिला स्तर से प्राप्त होने वाले शिक्षकों के विवरण के आधार पर ही मूल्यांकन केंद्रों में कार्य का विभाजन और जिम्मेदारियां तय की जाएंगी। अध्यक्ष ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि इस महत्त्वपूर्ण कार्य में किसी भी प्रकार की देरी पूरी मूल्यांकन प्रक्रिया को प्रभावित कर सकती है, जिसका सीधा असर परीक्षा परिणामों की घोषणा पर पड़ेगा।

30 अप्रैल तक आएगा बोर्ड परीक्षाओं का परिणाम

धर्मशाला, 23 मार्च (सुनील): हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने वार्षिक परीक्षाओं के परिणामों को समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से घोषित करने के लिए अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। बोर्ड ने इस वर्ष 30 अप्रैल तक परिणाम घोषित करने का लक्ष्य रखा है, जिसके लिए मार्च में आयोजित की जा रहीं 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं के दौरान ही उत्तरपुस्तिकाओं को एकत्रित करने का कार्य शुरू कर दिया जाएगा।

बोर्ड अध्यक्ष डा. राजेश शर्मा ने सभी जिला उपनिदेशालयों को कड़े निर्देश दिए हैं कि वे स्पॉट मूल्यांकन केंद्रों के लिए चयनित परीक्षकों की सूची आगामी 2 दिनों के भीतर बोर्ड को भेजें।

बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम समय पर देने की तैयारी

शिक्षा बोर्ड ने 2 दिनों में मांगी परीक्षकों की सूची

अनंत ज्ञान

◆ स्पॉट मूल्यांकन में देरी हुई तो जिला उप-निदेशालय होंगे जिम्मेदार : डॉ. राजेश

ब्यूरो, धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने वार्षिक परीक्षाओं के परिणामों को समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से घोषित करने की दिशा में अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। बोर्ड अध्यक्ष डॉ. राजेश शर्मा ने प्रेस वक्तव्य जारी कर प्रदेश के सभी जिला उप-निदेशालयों को कड़े निर्देश दिए हैं कि वे स्पॉट मूल्यांकन केंद्रों में ड्यूटी के लिए चयनित परीक्षकों की सूची आगामी दो दिन के भीतर बोर्ड को भेजना सुनिश्चित करें।

डॉ. शर्मा ने इस कार्य की गंभीरता पर जोर देते हुए कहा कि मूल्यांकन प्रक्रिया को सुचारु रूप से चलाने के लिए यह सूची एक आधारशिला की तरह है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिलास्तर से प्राप्त होने वाले परीक्षकों के विवरण के आधार पर ही मूल्यांकन केंद्रों में कार्य का विभाजन और जिम्मेदारियां तय की जाएंगी। अध्यक्ष ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि इस महत्वपूर्ण कार्य में किसी भी प्रकार की देरी पूरी मूल्यांकन प्रक्रिया को प्रभावित कर सकती है, जिसका सीधा असर परीक्षा परिणामों की घोषणा पर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए परिणामों को समय पर घोषित करना बोर्ड की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि जैसे ही जिलों से परीक्षकों की सूची प्राप्त होगी, बोर्ड बिना समय गंवाए उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया को आगे बढ़ा देगा। इससे न केवल मूल्यांकन कार्य निर्धारित समय में पूरा होगा, बल्कि पूरी प्रक्रिया सुगम और पारदर्शी भी बनी रहेगी।

उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों से अपेक्षा की कि वे बोर्ड द्वारा निर्धारित समय-सीमा का कड़ाई से पालन करें। उन्होंने अधिकारियों को इस कार्य को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं, ताकि मूल्यांकन का चरण बिना किसी बाधा के समय पर शुरू हो सके।

स्पॉट मूल्यांकन केंद्रों में ड्यूटी के लिए चयनित परीक्षकों की सूची दो दिन में भेजें

धर्मशाला, (आपका फैसला)। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने वार्षिक परीक्षाओं के परिणामों को समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से घोषित करने की दिशा में अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। बोर्ड अध्यक्ष डॉ. राजेश शर्मा ने एक प्रेस वक्तव्य जारी कर प्रदेश के सभी जिला उप-निदेशालयों को कड़े निर्देश दिए हैं कि वे स्पॉट मूल्यांकन केंद्रों में ड्यूटी के लिए चयनित परीक्षकों की सूची आगामी दो दिनों के भीतर बोर्ड को भेजना सुनिश्चित करें। डॉ. शर्मा ने इस कार्य की गंभीरता पर जोर देते हुए कहा कि मूल्यांकन प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए यह सूची एक आधारशिला की तरह है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिला स्तर से प्राप्त होने वाले परीक्षकों के विवरण के आधार पर ही मूल्यांकन केंद्रों में कार्य का विभाजन और जिम्मेदारियां तय की जाएंगी। अध्यक्ष ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि इस महत्वपूर्ण कार्य में किसी भी प्रकार की देरी पूरी मूल्यांकन प्रक्रिया को प्रभावित कर सकती है, जिसका सीधा असर परीक्षा परिणामों की घोषणा पर पड़ेगा। बोर्ड अध्यक्ष ने अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा कि छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए परिणामों को समय पर घोषित करना बोर्ड की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि जैसे ही जिलों से परीक्षकों की सूची प्राप्त होगी, बोर्ड बिना समय गंवाए उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया को आगे बढ़ा देगा। इससे न केवल मूल्यांकन कार्य निर्धारित समय में पूरा होगा, बल्कि पूरी प्रक्रिया सुगम और पारदर्शी भी बनी रहेगी। अंत में, डॉ. शर्मा ने सभी संबंधित अधिकारियों से अपेक्षा की कि वे बोर्ड द्वारा निर्धारित समय-सीमा का कड़ाई से पालन करें। उन्होंने अधिकारियों को इस कार्य को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं, ताकि मूल्यांकन का चरण बिना किसी बाधा के समय पर शुरू हो सके और छात्रों को अपने परीक्षा परिणामों के लिए अनावश्यक प्रतीक्षा न करनी पड़े।

24 MARCH , 2026 TUESDAY DHARAMSHALA

The Sunny Times

HP BOARD RACES AGAINST TIME: RESULTS PRIORITY ONE AS DR. RAJESH SHARMA SETS 48-HOUR DEADLINE

SUNNY MAHAJAN | DHARAMSHALA

The Himachal Pradesh Board of School Education (HPBOSE) is shifting into high gear to ensure that student results are delivered with both speed and "crystal-clear" transparency. In a decisive move to streamline the academic calendar, Board Chairman Dr. Rajesh Sharma has issued a formal mandate to all District Deputy Directorates, demanding the final list of designated evaluators for spot-marking centers within the next two days.

Dr. Sharma described the list of examiners as the "cornerstone" of the entire evaluation framework. He emphasized that the board cannot assign responsibilities or divide the workload until every district provides its details. His message was clear: there is no room for procrastination when the futures of thousands of students are hanging in the balance.

The Chairman noted that any lag at the district level creates a domino effect, potentially stalling the evaluation process and delaying the final scorecards. "Time and tide wait for no man," and for the HP Board, every hour counts toward their goal of a seamless rollout. Dr. Sharma reiterated that the board is ready to hit the ground running; as soon as the names arrive, appointment letters will be dispatched to ensure that marking begins without a hitch.

By setting this strict 48-hour window, the board is making it known that "procrastination is the thief of time." Dr. Sharma has called upon all education officials to treat this task as their top priority. The ultimate goal is to remove any hurdles from the evaluation phase so that students are not left in the dark, waiting unnecessarily for the results of their hard work.

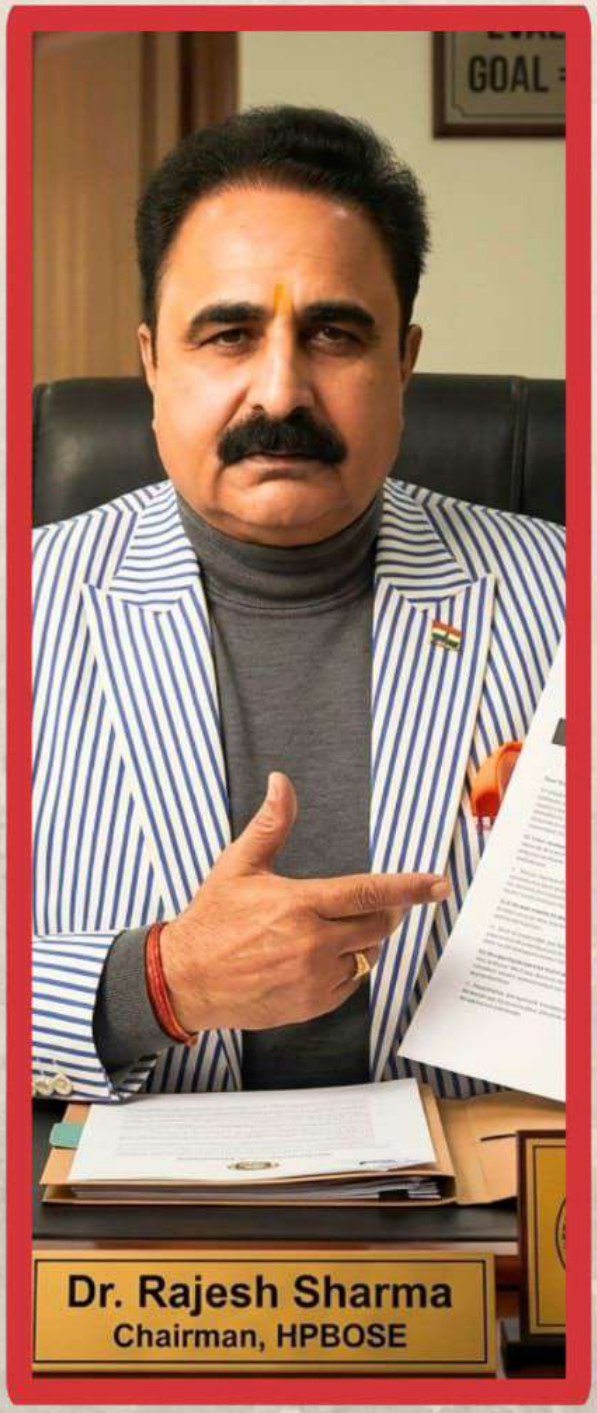

Education Board Delineates Work Distribution and Responsibilities at Evaluation Centers

Examination Results to be Declared on Time

SANJAY AGGARWAL

DHARAMSHALA MAR 23 : The Himachal Pradesh Board of School Education has intensified its efforts to ensure the timely and transparent declaration of annual examination results. Issuing a press statement, Board Chairman Dr. Rajesh Sharma has issued strict directives to all District Deputy Directorates across the state, instructing them to ensure that the list of teachers selected for duties at spot evaluation centers is submitted to the Board within the next two days. Emphasizing the critical nature of this task, Dr. Sharma stated that this list serves as a cornerstone for the smooth execution of the evaluation process. He clarified that the division of work and the allocation of responsibilities at the evaluation centers will be determined solely based on the details of the teachers received from the district level. The Chairman issued a stern warning, noting that any delay in this crucial task could jeopardize the entire evaluation process, thereby directly impacting the timely declaration of examination results. Reaffirming his commitment, the Board Chairman stated that declaring results on time—with the students' future in mind—remains the Board's utmost priority. He further informed that as soon as the lists of teachers are received from the districts, the Board will proceed with their appointment process without delay. This will not only ensure the completion of evaluation work within the stipulated timeframe but also maintain the overall process as both seamless and transparent. Dr. Sharma expressed his expectation that all concerned officials would strictly adhere to the timelines established by the Board. He directed the officials to complete this task on a priority basis so that the evaluation phase may commence on time and without any impediments, thereby sparing students from having to endure an unnecessary wait for their examination results.

बदलाव

विद्यार्थियों के स्किल्स का पूरा रिकॉर्ड होगा दर्ज, नौकरी और स्वरोजगार में मिलेगा फायदा

वोकेशनल में 9वीं से 12वीं तक अलग मिलेगा सर्टिफिकेट

विपिन चौधरी

धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब बोर्ड के तहत पढ़ने वाले विद्यार्थियों को वोकेशनल विषयों के लिए अलग से सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा।

इस सर्टिफिकेट में 9वीं से 12वीं तक विद्यार्थियों की ओर से किए अध्ययन, प्रशिक्षण और कौशल का पूरा ब्योरा दर्ज होगा। इससे उनके स्किल्स की पहचान हो सकेगी। शिक्षा बोर्ड की ओर से 9वीं से 12वीं तक पढ़ाए जाने वाले वोकेशनल विषयों की पढ़ाई के बाद इसका सर्टिफिकेट पूरी तरह से अलग होगा। इसे हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से जारी किया जाएगा।

हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से जारी सर्टिफिकेट की मान्यता अंतरराष्ट्रीय स्तर की होगी। अलग सर्टिफिकेट मिलने से छात्रों को नौकरी, स्वरोजगार और उच्च शिक्षा में अपने कौशल को बेहतर तरीके से प्रस्तुत करने का अवसर मिलेगा।

ड्यूल स्टेटस मिलने से बोर्ड शुरू करेगा व्यावसायिक कोर्स

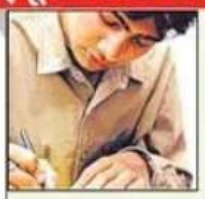

स्कूल शिक्षा बोर्ड को एनसीवीटी से ड्यूल स्टेटस मिला है। इसके चलते अब शिक्षा बोर्ड जहां वोकेशनल विषयों को अपने हिसाब से शुरू कर सकेगा, वहीं उनकी थ्योरी, प्रैक्टिकल और परीक्षाएं करवाने का जिम्मा भी शिक्षा बोर्ड के पास होगा। इसके चलते शिक्षा बोर्ड 2026-27 से बागबानी की पढ़ाई शुरू करने जा रहा है। दूसरे वोकेशनल विषय आगामी सत्रों में शुरू किए जाएंगे। इनकी रूपरेखा तैयार करने में स्कूल शिक्षा बोर्ड जुटा है।

> स्कूल शिक्षा बोर्ड को एनसीवीटी से ड्यूल स्टेटस मिला है। इसके चलते अब शिक्षा बोर्ड के तहत व्यावसायिक कोर्स शुरू किए जाएंगे। इन व्यावसायिक कोर्सों को पढ़ने वाले अभ्यर्थियों को अलग से संबंधित व्यावसायिक कोर्स का सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा।
>
> **- डॉ. मेजर विशाल शर्मा,** सचिव, स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला